भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3385
उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

अज/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों में अधिगम स्तर

3385. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**
श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को समाचार पत्र में हाल ही में प्रकाशित उस रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें यह खुलासा किया गया है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में 40 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण छात्र ग्रेड-स्तर के प्रश्नों का भी उत्तर देने में असमर्थ हैं;
(ख) यदि हां, तो विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं और पहलों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कम अधिगम परिणामों के क्या कारण हैं;
(ग) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के अधिगम स्तर की वर्तमान स्थिति क्या है;
(घ) विशेषकर उत्तर प्रदेश में अध्यापक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम संवर्धन और अवसंरचना विकास सहित शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि ग्रामीण छात्र आगामी पांच वर्षों में ग्रेड-अनुकूल अधिगम स्तर प्राप्त कर सकें?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): एनएएस-2017 और एनएएस-2021 की रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित ग्रामीण छात्रों का अधिगम स्तर **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): शिक्षा मंत्रालय शिक्षा प्रणाली की स्थिति के एक संकेतक के रूप में बच्चों की प्रगति और अधिगम क्षमताओं का आकलन करने और विभिन्न स्तरों पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु उचित कदम उठाने के लिए तीन वर्ष के अंतराल पर कक्षा 3, 5, 8 और 10 में नमूना आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का एक रोलिंग कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। एनएएस का अंतिम

राउंड दिनांक 04.12.2024 को आयोजित किया गया था और उसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है। वर्ष 2017 और वर्ष 2021 में किए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण ने शहरी और ग्रामीण स्कूलों के बीच उपलब्धियों के स्तर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दर्शाया है।

(ग): सामाजिक समूह (एससी/एसटी/ओबीसी) के आधार पर उत्तर प्रदेश के छात्रों के ग्रेड-वार, विषय-वार प्रदर्शन की तुलना करने वाले एनएएस 2017 और एनएएस 2021 के परिणाम **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र ग्रामीण, वंचित और अल्पसुविधा प्राप्त छात्रों सहित देश के छात्रों की शैक्षिक स्थिति के उत्थान का प्रयास करते हैं। मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अनुरूप बनाया गया है। एनईपी 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र जन्म या पृष्ठभूमि के आधार पर अधिगम और उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर न खोए। इसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के सरोकारों को ध्यान में रखा गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भौगोलिक पहचान वाले जैसे गांवों, छोटे शहरों, आकांक्षी जिलों और अन्य श्रेणियों के छात्र शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य पहुंच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना है।

समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न पहलों जैसे कि नई शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना की शुरूआत, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान तथा छात्र विकास के लिए परिवर्तनकारी मूल्यांकन, अनुभवात्मक और योग्यता आधारित अधिगम, शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को सेवाकालीन प्रशिक्षण, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन, अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों हेतु अनुदान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, आईसीटी और डिजिटल पहल के लिए सहायता, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण आदि हेतु सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें सतत अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

राष्ट्रीय बोध पठन एवं संख्याज्ञान दक्षता पहल (निपुण भारत) दिनांक 5 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक आवश्यक रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान प्राप्त कर ले। यह मिशन 5+3+3+4 शैक्षणिक संरचना के स्कूल निरंतरता के प्रथम 5 वर्षों को कवर करता है, जिसमें 3 प्री-स्कूल वर्ष भी शामिल हैं।

शिक्षकों को सतत अधिगम के अवसर प्रदान करने के लिए दीक्षा (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अक्टूबर 2020 में निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय पहल) प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया ताकि प्राथमिक शिक्षकों तक पहुंच बनाई जा सके और इसका विस्तार सभी स्तर के शिक्षकों तक किया जा सके। इसमें बातचीत के लिए कई दृष्टिकोण जैसे कि वीडियो के साथ-साथ टेक्स्ट मॉड्यूल शामिल हैं। इस सभी सामग्री को बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) के विकासात्मक लक्ष्यों और अधिगम परिणामों के अनुरूप बनाया गया हैं।

आंगनवाड़ियों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) शिक्षकों का प्रारंभिक कैडर तैयार करने के लिए जुलाई, 2022 में निष्ठा-ईसीसीई और एफएलएन का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त शिक्षाशास्त्र के संबंध में मास्टर प्रशिक्षकों को जागरूक बनाना है, जो बुनियादी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने में योगदान देगा। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्री-स्कूल शिक्षकों दोनों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

एनईपी 2020 में इन संस्थानों की क्षमता और कार्य संस्कृति में बदलाव लाने और उन्हें उत्कृष्टता के जीवंत संस्थानों के रूप में विकसित करने के लिए डीआईईटी पर पुनः बल देने की बात की गई है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से देश के सभी 613 कार्यात्मक डीआईईटी के वास्तविक उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 में 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 92,320.18 लाख रुपये के अनुमानित बजट के साथ 125 डाइट को मंजूरी दी गई थी।

केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पीएम श्री (पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) योजना दिनांक 7 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना है और समय के साथ उदाहरणपरक स्कूल के रूप में उभरना है, तथा पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है, जिनमें से अब तक 12,084 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) की केंद्र प्रायोजित योजना को नया रूप दिया गया है और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के अतिरिक्त बालवाटिका के छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह स्कूल पोषण उद्यान (एसएनजी) की स्थापना और 'तिथि भोजन' के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करने को प्रोत्साहित करती है।

*****

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य श्री धर्मेन्द्र यादव एवं श्री चरनजीत सिंह चन्नी द्वारा 'अज/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों में अधिगम स्तर' के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3385 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एनएएस 2017 और एनएएस 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के ग्रेड-वार और विषय-वार प्रदर्शन की तुलना संबंधी डेटा

राष्ट्रीय स्तर:

ग्रेड 3				
विषय	एनएएस 2017		एनएएस 2021	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
भाषा	68	67	62	61
गणित	64	64	58	56
ईवीएस	65	65	58	56
ग्रेड 5				
विषय	एनएएस 2017		एनएएस 2021	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
भाषा	58	59	55	56
गणित	55	52	44	43
ईवीएस	57	56	49	48
ग्रेड 8				
विषय	एनएएस 2017		एनएएस 2021	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
भाषा	57	57	50	58
गणित	43	39	36	37
विज्ञान	45	41	38	42
सामाजिक विज्ञान	45	42	39	40

एनएएस 2017 और एनएएस 2021 में पंजाब और उत्तर प्रदेश से स्थान के अनुसार छात्रों के ग्रेड-वार और विषय-वार प्रदर्शन की तुलना संबंधी डेटा

पंजाब:

ग्रेड 3				
विषय	एनएएस 2017		एनएएस 2021	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
भाषा	64	62	76	73
गणित	56	56	72	69
ईवीएस	58	56	70	69
ग्रेड 5				
विषय	एनएएस 2017		एनएएस 2021	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
भाषा	53	54	70	68
गणित	47	46	58	56
ईवीएस	51	51	61	58

ग्रेड 8				
विषय	एनएएस 2017		एनएएस 2021	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
भाषा	54	55	66	68
गणित	31	32	50	49
विज्ञान	37	36	50	50
सामाजिक विज्ञान	35	34	50	48

उत्तर प्रदेश:

ग्रेड 3				
विषय	एनएएस 2017		एनएएस 2021	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
भाषा	58	54	58	56
गणित	59	60	54	51
ईवीएस	56	54	55	52
ग्रेड 5				
विषय	एनएएस 2017		एनएएस 2021	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
भाषा	51	50	52	52
गणित	51	50	42	39
ईवीएस	53	52	47	44
ग्रेड 8				
विषय	एनएएस 2017		एनएएस 2021	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
भाषा	53	50	46	52
गणित	41	34	33	33
विज्ञान	43	35	35	37
सामाजिक विज्ञान	43	36	36	36

*****

अनुलग्नक-II

माननीय संसद सदस्य श्री धर्मेन्द्र यादव एवं श्री चरनजीत सिंह चन्नी द्वारा 'अज/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों में अधिगम स्तर' के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3385 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एनएएस 2017 और एनएएस 2021 में सामाजिक समूह द्वारा छात्रों के ग्रेड-वार और विषय-वार प्रदर्शन की तुलना संबंधी डेटा

राष्ट्रीय स्तर:

ग्रेड 3						
विषय	एनएएस 2017			एनएएस 2021		
	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी
भाषा	67	66	68	62	61	62
गणित	64	62	65	57	55	57
ईवीएस	64	63	66	58	57	57
ग्रेड 5						
विषय	एनएएस 2017			एनएएस 2021		
	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी
भाषा	57	55	60	54	53	54
गणित	53	51	56	43	41	43
ईवीएस	56	55	58	48	47	48
ग्रेड 8						
विषय	एनएएस 2017			एनएएस 2021		
	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी
भाषा	55	53	58	49	47	51
गणित	40	40	44	35	33	35
विज्ञान	43	43	46	37	36	38
सामाजिक विज्ञान	42	43	45	38	37	39

उत्तर प्रदेश (सामाजिक समूह द्वारा):

ग्रेड 3						
विषय	एनएएस 2017			एनएएस 2021		
	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी
भाषा	59	57	57	57	58	58
गणित	59	57	59	53	52	54
ईवीएस	56	55	55	54	53	54
ग्रेड 5						
विषय	एनएएस 2017			एनएएस 2021		
	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी
भाषा	51	42	52	51	51	52
गणित	50	41	51	41	40	41
ईवीएस	53	43	54	46	45	46
ग्रेड 8						
विषय	एनएएस 2017			एनएएस 2021		
	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी
भाषा	53	49	54	44	43	46
गणित	41	36	41	32	32	33
विज्ञान	42	38	42	34	34	35
सामाजिक विज्ञान	42	38	42	35	34	36

*****